

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5335
उत्तर देने की तारीख 03.04.2025

ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स

5335. श्री चंदन चौहानः:

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदंड प्रस्तावित हैं कि पचास प्रतिशत व्यवसाय महिलाओं द्वारा संचालित हों;
(ख) इस पहल के विभिन्न पहलुओं जैसे वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए 277.35 करोड़ रुपये का बजट किस प्रकार आवंटित किया जाएगा; और
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रारंभिक समर्थन चरण से आगे भी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) का उपयोग करना जारी रखें?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एमएसएमई मंत्रालय के एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन (एमएसएमई टीम पहल) का उद्देश्य ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के सहयोग से देश में एमएसएमई के बीच ई-कॉमर्स का प्रचार करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 50% लाभार्थी उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले हों, जो मानदंड अपनाया जा रहा है वह यह है कि उद्यम को मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर महिला स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इस स्कीम का लक्ष्य 5,00,000 एमएसई को लाभ पहुंचाना है, जिनमें से 2,50,000 लाभार्थी महिला उद्यमी होंगी।

(ख) एमएसएमई टीम पहल के लिए 277.35 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का घटक-वार आवंटन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	एमएसएमई टीम पहल का घटक	परिव्यय (करोड़ रु. में)
1	जागरूकता सृजन और मांग सृजन	14.875
2	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को शामिल करना एवं सूचीकरण	125
3	पोर्टल पर खाता प्रबंधन सहायता, परिवहन और पैकेजिंग सब्सिडी, पैकेजिंग डिजाइन और एआई कैटलॉगिंग सहायता	108.91
4	पोर्टल विकास और प्रशासन लागत	28.565
	कुल	277.35

(ग) ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाले एमएसएमई को ओएनडीसी पर विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों (एसएनपी) के माध्यम से शामिल करने और खाता प्रबंधन में सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें पोर्टल पर अपने ई-कॉमर्स परिचालन को जारी रखने और बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी।
